कानपुर, मंगलवार, 9 जून, 2026
वर्ष: 03, अंक: 141, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड यूपी में मजदूरों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता...>Pg10

10 करोड़ के गांजे के साथ ट्रक पकड़ा..>Pg03

मूल्य: 2 ₹

पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट का 'प्रहार'

24 घंटे से ज्यादा गैरकानूनी हिरासत को बताया संविधान पर हमला, दोषी अफसरों के वेतन से वसूली तक के दिए संकेत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

प्रयागराज। नागरिक स्वतंत्रता और पुलिस जवाबदेही को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था के लिए बड़ा चेतावनी संदेश माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक गैरकानूनी हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद-21 का खुला उल्लंघन है और इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सरकार चाहे तो मुआवजे की रकम संबंधित दोषी पुलिसकर्मी के वेतन से भी वसूल सकती है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी मतंबर मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सख्त टिप्पणी की। अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 25 हजार रुपये अंतरिम मुआवजा और 10 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया। साथ ही प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट समेत प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरेट को आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को 14 सितंबर तक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

पूरा मामला वर्ष 2022 का है। याचिका के अनुसार घरेलू विवाद के दौरान चौकी प्रभारी सूर्य प्रकाश दुबे मतंबर मिश्रा को उनके घर से केवल लुंगी-कुर्ता की हालत में उठाकर चौकी ले गए और लगभग 24 घंटे तक लॉकअप में रखा। आरोप यह भी लगाया गया कि रिहाई के बदले 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई। इस दौरान न तो उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई और न ही समय पर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान संबंधित दरोगा ने अदालत में दावा किया कि मिश्रा स्वयं समझौते के लिए चौकी पहुंचे थे। इस पर हाईकोर्ट ने बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी न तो पंच परमेश्वर हैं और न ही पारिवारिक विवादों के मध्यस्थ। अदालत ने कहा कि कई पुलिस अधिकारी यह मान बैठते हैं कि उनके गलत कार्यों को कोई चुनौती नहीं देगा और आम नागरिक न्यायालय तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है।

कोर्ट ने यह भी पाया कि हिरासत के दो दिन बाद मतंबर मिश्रा के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। अदालत ने कहा कि ये धाराएं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हैं, न कि घरेलू विवादों को निपटाने या अवैध हिरासत को वैध ठहराने के लिए। अदालत ने पुलिस की इस कार्रवाई को कानून के दुरुपयोग की श्रेणी में माना।

महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किसी मुआवजे की मांग तक नहीं की थी। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने कहा कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो राहत देना अदालत का संवैधानिक दायित्व बन जाता है। अदालत ने दो टूक कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च संवैधानिक मूल्य है और पुलिस मनमानी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में पुलिस कार्यप्रणाली पर गहरा असर डालेगा। प्रदेश में अक्सर घरेलू विवाद, जमीन विवाद या स्थानीय तनाव के मामलों में लोगों को घंटों चौकी या थाने में बैठाए रखने के लिए धारा 107/116 का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पुलिस को हर हिरासत का स्पष्ट कानूनी आधार रिकॉर्ड में रखना होगा।

अदालत की सबसे सख्त टिप्पणी वेतन से वसूली को लेकर मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि भविष्य में मानवाधिकार उल्लंघन या अवैध हिरासत साबित होती है तो संबंधित अधिकारी केवल विभागीय कार्रवाई ही नहीं, बल्कि आर्थिक दंड के भी दायरे में आएंगे।

107/116 के दुरुपयोग पर न्यायिक शिकंजा

अक्सर पुलिस शांति भंग की आशंका दिखाकर लोगों को घंटों थाने में बैठाए रखती है। अदालत ने संकेत दिया कि अब ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा अधिक सख्ती से होगी।

घरेलू विवादों में पुलिस की भूमिका सीमित

कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, पारिवारिक समझौते कराना नहीं। यह टिप्पणी भविष्य में पुलिस हस्तक्षेप की सीमाएं तय कर सकती है।

निचली अदालतों और थानों पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि फैसले के बाद थानों में गिरफ्तारी, हिरासत और शांति भंग की कार्रवाई के रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित रखना अनिवार्य हो जाएगा।

- हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत को सीधे अनुच्छेद-21 का उल्लंघन माना।
- दोषी पुलिसकर्मियों के वेतन से वसूली के संकेत सबसे बड़ी टिप्पणी मानी जा रही।
- घरेलू विवाद में 107/116 लगाने पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई।
- पुलिस अधिकारियों को पंच परमेश्वर समझने की मानसिकता पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी।
- सभी पुलिस कमिश्नरेट को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश।
- प्रयागराज पुलिस आयुक्त को 14 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
- फैसले को उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार और मानवाधिकार सुरक्षा की दिशा में बड़ा न्यायिक हस्तक्षेप माना जा रहा है।

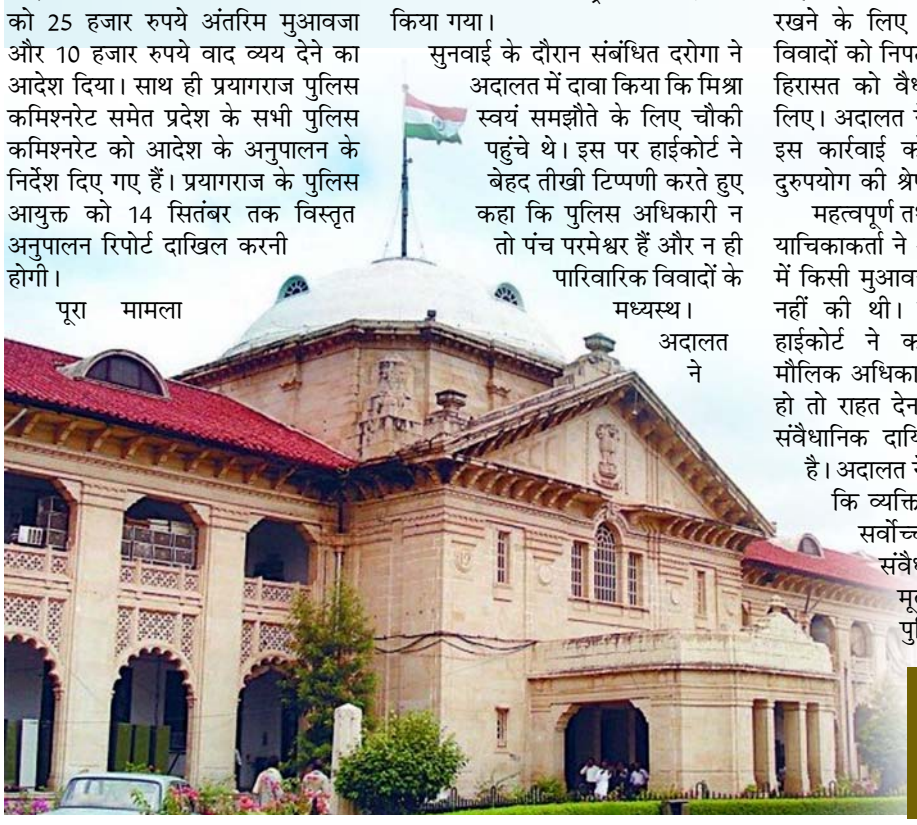

अनुच्छेद-21 की नई व्याख्या

हाईकोर्ट ने साफ किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल कानूनी शब्द नहीं बल्कि संविधान की मूल आत्मा है। 24 घंटे से अधिक हिरासत बिना वैध प्रक्रिया के सीधे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानी जाएगी।

वेतन से वसूली क्यों अहम

सरकारी धन से मुआवजा देने के बजाय दोषी अफसर के वेतन से राशि वसूलने की टिप्पणी पुलिस तंत्र में व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

20 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई रिहाई के बदले।

25 हजार रुपये अंतरिम मुआवजा और 10 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश।

आघू मोड़ की करोड़ों रुपयों की जमीन पर माफियाओं का खेला

आर. एस. त्रिवेदी स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। जनपद के अकबरपुर कस्बे में करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि पर कथित तौर पर कूटरचित अभिलेखों और प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के बल पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार पिछले छह वर्षों से न्याय की आस में अधिकारियों के दफ्तरों की चौखट पर भटक रहा है, लेकिन अब तक उसे राहत नहीं मिल सकी है। वार्ड नंबर-16 कन्हैया नगर, आघू मोड़ निवासी छोटेलाल पुत्र स्व. बाबूलाल का आरोप है कि बहुमूल्य भूमि को सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़प लिया गया। पीड़ित का कहना है कि राजस्व अभिलेखों में आज भी संपत्ति उसके परिवार के नाम दर्ज है, इसके बावजूद विवादित भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराया गया।

» आरोप हैं कि कूटरचित अभिलेखों के सहारे करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप

» पुराने अभिलेखों में यह जमीन नवीन प्रति के रूप में दर्ज रही है

दो मंजिल ईमारत

पिस्टल लगा कर पहुंचे थे युवक

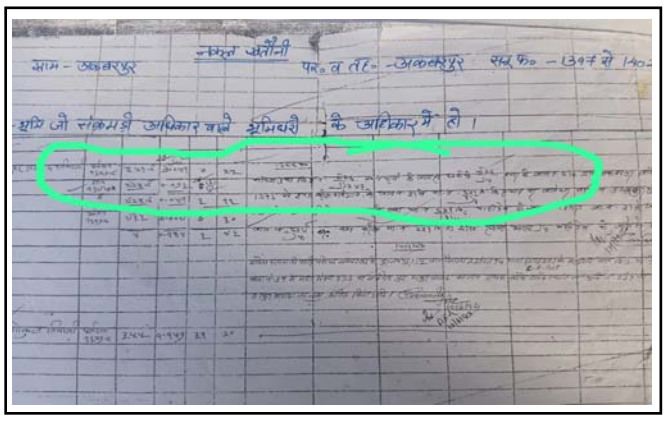

छोटेलाल के अनुसार वर्ष 2020 से भूमि पर कब्जे के प्रयास शुरू हुए और धीरे-धीरे कथित रूप से फर्जी कागजातों के आधार पर जमीन पर दावा प्रस्तुत किया गया। पीड़ित का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव और प्रशासनिक उदासीनता के चलते वर्ष 2026 तक विवादित भूमि पर दो मंजिला निर्माण खड़ा कर दिया गया।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि भूमि पर मौजूद वर्षों पुराने आम, अमरूद और नीम के हरे-भरे पेड़ों को भी काट दिया गया, जिससे न केवल उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा बल्कि पर्यावरणीय नियमों की भी अनदेखी की गई।

सबसे गंभीर बात यह है कि भूमि विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि तहसील, पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य सक्षम अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

छोटेलाल ने कुछ राजस्व कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उसका कहना है कि यदि अभिलेखों और भूमि संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच कराई जाए तो बड़े खुलासे हो सकते हैं।

न्याय की उम्मीद में पीड़ित ने अब उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या बाहरी राजस्व अधिकारियों से कराने की मांग उठाई है।

उठ रहे हैं कई सवाल

» यदि राजस्व अभिलेखों में नाम किसी और का दर्ज है तो कब्जे और निर्माण की अनुमति कैसे मिली?

» यदि भूमि विवाद न्यायालय में लंबित है तो निर्माण कार्य क्यों नहीं रोका गया?

» यदि कूटरचित अभिलेखों का उपयोग हुआ है तो इसकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई?

» यदि हरे पेड़ों की कटान हुई है तो संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की?

» मामले ने एक बार फिर भू-माफियाओं, फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के खेल और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। अब निगाहें जिला प्रशासन और शासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।

निर्माण कार्य जारी

नया मीटर लगा

10 करोड़ के गांजे के साथ ट्रक पकड़ा
अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

'से नो टू ड्रग्स' अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और रावतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 600 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर पुलिस को सोमवार देर रात मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'से नो टू ड्रग्स' के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच और रावतपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 600 किलो से अधिक मादक पदार्थ से लदे ट्रक को पकड़कर अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक व तस्कर लियाकत अली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

पुलिस के मुताबिक सोमवार देर रात सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर एक ट्रक कानपुर से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और रावतपुर पुलिस की टीमें सक्रिय हो गईं और संदिग्ध ट्रक की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुलिस को संदिग्ध ट्रक दिखाई दिया, लेकिन रुकने का इशारा करने पर चालक ट्रक लेकर भागने लगा।

इसके बाद पुलिस ने करीब 15 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया। जीटी रोड पर घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया गया। तलाशी लेने पर ट्रक से 600 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद हुआ। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी लियाकत अली ने बताया कि वह हरियाणा का रहने वाला है और खेप उड़ीसा से आगरा ले जाई जा रही थी। रास्ते में विभिन्न महानगरों में इसकी सप्लाई की जानी थी।

पुलिस पूछताछ में जमशेद, जावेद और जुनैद नाम के लोगों का भी खुलासा हुआ है। एडीसीपी क्राइम सुमित रामटेके ने बताया कि मामला संगठित अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

संगीत टॉकीज चौराहे पर प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, धुएं से छाया अंधेरा

संवराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। शहर के व्यस्त संगीत टॉकीज चौराहे के पास स्थित एक प्लास्टिक कुर्सी गोदाम में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि गोदाम से उठते काले धुएं का घना गुबार आसमान में फैल गया और कुछ देर के लिए आसपास की सड़क पर अंधेरे जैसी स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही गोदाम से तेज लपटें उठने लगीं। प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और धुएं ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई। एहतियात के तौर पर पुलिस ने कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित क्षेत्र से डायवर्ट कराया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में दमकल विभाग की करीब आठ गाड़ियों को आग बुझाने में लगाया गया। फायर फाइटर्स ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि गोदाम में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

> ⇨ **आठ दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू, आग के कारणों की जांच शुरू**

दमकल कर्मियों ने आसपास की इमारतों तक आग फैलने से रोकने के लिए लगातार पानी की बौछारें कीं। मौके पर भारी भीड़ जमा होने के कारण बचाव कार्य में शुरुआती दिक्कतें भी सामने आईं।

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है, लेकिन अधिकारी जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रहे हैं। पुलिस और फायर विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है।

सत्ता के रसूख में चूर विधायक का पीआरओ फिर चर्चा में!

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर की घाटमपुर विधानसभा से अपना दल (एस) विधायक सरोज कुरील के पीआरओ मनीष तिवारी एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में हैं। ताजा मामला घाटमपुर के रार गांव का है, जहां कार पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर मनीष तिवारी अपने साथियों के साथ मिलकर एक सफेद रंग की कार पर पत्थरों और डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं।

पीड़ित ग्रामीण प्रतीक मिश्रा का आरोप है कि मनीष तिवारी ने उन्हें तुरंत कार हटाने को कहा और कुछ ही देर बाद पर उन पर और उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला बोल दिया।

दूसरी ओर, मनीष तिवारी ने इन आरोपों को नकारते हुए दूसरे पक्ष पर मारपीट करने और उनका हाथ तोड़ने का आरोप लगाया है। इस वक्त दोनों पक्षों ने घाटमपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

अपराधिक इतिहास और पुराना रसूखः यह पहला मौका नहीं है जब मनीष तिवारी अपनी विवादित छवि को लेकर चर्चा में आए हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वह विधायक के संरक्षण और रसूख के बल पर क्षेत्र में लगातार दबंगई दिखाते हैं। सन 2007 से 2023 के बीच मनीष तिवारी पर गुंडा एक्ट सहित पांच से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक प्रशासन द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर जनता में आक्रोश है।

घटना की सीसीटीवी फुटेज

स्वराज इंडिया

स्वराज इंडिया आसपास 07

राजनीति की चक्की में पिसता न्याय गाड़ी विधायिका की आरोपी अज्ञात

स्वराज इंडिया

स्वराज इंडिया उन्नाव 06

नशे में रफ्तार का कहरः विधायिका की कार से उड़ गईं रक्षाबंधन की खुशियां

उन्नाव का वो दर्दनाक हादसा

इस घटना से महज कुछ महीनों पहले ही मनीष तिवारी पर एक बेहद गंभीर आरोप लगा था। आरोप था कि उन्होंने नशे की हालत में विधायक की कार से कानपुर से सटे उन्नाव जिले में एक बाइक सवार युवक निखिल गुप्ता उर्फ आशु को टक्कर मार दी थी, जिसमें निखिल की मौत हो गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सत्ता और रसूख के दबाव में उस बेहद संवेदनशील मामले में भी मनीष को बचा लिया गया। राजनीतिक संरक्षण के चलते बार-बार बच निकलने की इस परिपाटी ने एक बार फिर स्थानीय कानून व्यवस्था और प्रशासनिक इकबाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना यह होगा कि इस बार सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाता है।

दिल्ली बेसमेंट अग्निकांड के बाद केडीए सख्त

अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

20 बेसमेंट संचालकों को नोटिस

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। दिल्ली में हुए दर्दनाक बेसमेंट अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माणों और बेसमेंट के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक के निर्देश और सचिव के आदेश पर मंगलवार को प्रवर्तन जोन-1बी की टीम ने बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की। प्रवर्तन दल ने ग्राम बगदौदी कछार स्थित अराजी संख्या 27, 28 एवं 33 में लगभग 12 बीघा क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह प्लाटिंग हरिओम द्विवेदी, श्याम अवस्थी, अनुपम दुबे एवं अन्य लोगों द्वारा कराई गई थी।

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

इसके अलावा लखनपुर स्थित गुरुदेव चौराहे के पास प्लॉट संख्या 53 पार्ट पर अमित शुक्ला द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के कराए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया। वहीं शुक्लागंज में पीटर इंग्लैंड शोरूम के बगल में अंकित मिश्रा द्वारा कराए जा रहे निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

प्रवर्तन अभियान प्रभारी संदीप मोदनवाल के नेतृत्व में अवर अभियंता हिमांशु बर्नवाल, सुपरवाइजर लाल सिंह, राम अवतार, राजकुमार तथा प्रवर्तन दस्ते की मौजूदगी में संपन्न हुआ।

कार्रवाई के दौरान तातियागंज स्थित शिवरानी विहार फेज-1 एवं फेज-4, श्याम कुंज सोसाइटी फेज-2 तथा राधा ग्रीन्स सोसाइटी सहित कई अवैध प्लाटिंग और निर्माणों को नोटिस जारी किए गए।

20 बेसमेंट संचालकों को चेतावनी

दिल्ली बेसमेंट अग्निकांड से सबक लेते हुए केडीए ने बेसमेंट में संचालित होटल, दुकान और ओपीडी को तत्काल बंद एवं खाली कराने के लिए 20 नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में बेसमेंट खाली नहीं किए जाने पर संबंधित परिसरों को सील कर दिया जाएगा।

केडीए प्रवर्तन अधिकारी संदीप मोदनवाल ने बताया कि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग अथवा सामग्री भंडारण के लिए किया जाना चाहिए।

साथ ही होटलों की फायर सेफ्टी एनओसी की भी लगातार जांच की जा रही है ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।

प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल स्वीकृत कॉलोनियों में ही भूखंड खरीदें तथा अवैध प्लाटिंग से बचें, जिससे शहर के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिल सके।

एक फोन कॉल से खुलेगी रुकी पेंशन की राह, 21 हजार पेंशनरों को बड़ी राहत

» डीएलसी न जमा होने से बंद थी पेंशन, अब डाकिया घर पहुंचकर बनाएगा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पेंशन पाने वाले हजारों पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कानपुर रीजन में जीवन प्रमाणपत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट-डीएलसी) जमा न होने के कारण जिन 21 हजार से अधिक पेंशनरों की पेंशन रुकी हुई थी, उन्हें अब घर बैठे यह सुविधा मिलने लगी है। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के सहयोग से शुरू की गई विशेष मुहिम के तहत एक फोन कॉल पर डाकिया घर पहुंचकर डीएलसी तैयार कर रहा है, जिससे रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू की जा रही है।ईपीएफओ के अनुसार कानपुर रीजन में कुल 87,292 पेंशनर हैं। इनमें 21,374 ऐसे पेंशनर हैं जिनकी डीएलसी जमा न होने के कारण पेंशन भुगतान बंद हो गया था। इसके अलावा 9,193 पेंशनर ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले पांच वर्षों या उससे अधिक समय से पेंशन नहीं ली है। अब इनकी स्थिति का पता लगाने और पात्र लोगों तक पेंशन पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

ईपीएफओ ने आईपीपीबी के साथ हुए समझौते के तहत डाक विभाग को ऐसे पेंशनरों की पहचान और सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक डाकिये को अपने क्षेत्र में चिन्हित पेंशनरों तक पहुंचकर उनका डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार करना है। यदि पेंशनर जीवित हैं तो उनकी रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी।

इस अभियान का लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जिनके पेंशनर सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे मामलों में आश्रितों को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल पा रही थी। नौबस्ता निवासी राजीव कुमार का मामला इसका उदाहरण है। दो वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन डीएलसी जमा न होने से उनकी पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। डाक विभाग की सहायता से जानकारी मिलने के बाद परिवार ने टोल फ्री नंबर 033-22029000 पर संपर्क किया, जिसके बाद विधवा और बच्चों को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को आजीवन पेंशन मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति तथा निर्धारित आयु तक बच्चों को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन एक हजार रुपये निर्धारित है। अधिकारियों का कहना है कि घर-घर डीएलसी अभियान से हजारों पात्र पेंशनरों और उनके आश्रितों को राहत मिलेगी तथा लंबे समय से अटकी पेंशन का भुगतान जल्द शुरू हो सकेगा।

गंगापुल पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर, एसबीआई कर्मी बाल-बाल बचे

» उन्नाव ड्यूटी जा रहे बैंक कर्मचारियों की कार रेलिंग पर चढ़ी, तीन किलोमीटर लंबा जाम लगा

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर-उन्नाव सीमा पर स्थित गंगापुल पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा होते-होते टल गया। उन्नाव के गगनखेड़ा स्थित एसबीआई शाखा में ड्यूटी पर जा रहे दो बैंक कर्मियों की कार ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित होकर पुल की सुरक्षा रेलिंग पर चढ़ गई।

गनीमत रही कि दोनों कर्मचारियों की जान बच गई।

चकेरी के श्यामनगर निवासी एसबीआई कर्मचारी अमित शर्मा अपने सहकर्मी निशांत शर्मा के साथ कार से उन्नाव जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार रेलिंग पर जा अटकी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत दोनों को कार से बाहर निकाला। लोगों का कहना था कि यदि सुरक्षा रेलिंग न होती तो कार गंगा नदी में गिर सकती थी।हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के चलते रामादेवी से उन्नाव की ओर जाने वाले फ्लाईओवर और गंगापुल पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भीषण गर्मी में फैक्ट्रीकर्मी, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और अन्य यात्री लंबे समय तक फंसे रहे। सूचना पर पहुंची यातायात पुलिस ने करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद क्रेन से क्षतिग्रस्त कार हटवाई। टीएसआई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि फरार ट्रक चालक की पहचान कर कार्रवाई की जा रही।

सम्पादकीय

विकास की प्राथमिकताओं में हो सावधानी

आज वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से अनिश्चितता के भंवर में फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका-इस्त्राइल व ईरान के बीच जारी संघर्ष से उपजा भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि, बाधित व्यापार मार्ग से प्रभावित आपूर्ति श्रृंखला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। ऐसे में देश के लिये प्राथमिकता केवल विकास की गति बनाये रखना ही नहीं होनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि आम लोगों को महंगाई की मार से बचाने के लिये व्यावहारिक कदम भी उठाये। दरअसल, भारत के सामने केवल मध्यपूर्व में जारी संघर्ष से उपजा संकट ही नहीं है, बल्कि अंदरूनी मोर्चे पर भी कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने देश में मानसून में कमी की आशंका जतायी है। ऐसा अल-नीनो के प्रभाव के चलते पैदा होने वाले विषम हालातों के चलते कहा गया है। जिसके चलते आगामी कुछ माह में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। ऐसे में महंगाई में कमी आने की सूरत नजर नहीं आती। देश के कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता आर्थिक विकास में वृद्धि ही है। जिसके चलते आशंका जतायी जा रही है कि इससे नागरिकों पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। निस्संदेह, अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए आम आदमी को महंगाई से राहत देना बेहद जरूरी है। अन्यथा आम लोगों का जीवन-यापन और अधिक कष्टकारी भी हो सकता है। यही वजह है कि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं व महंगाई नियंत्रण के प्रयासों के बीच संतुलन साधने का प्रयास करे। लेकिन पिछले दिनों पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कई बार की वृद्धि के बाद व्यावसायिक व घरेलू एलपीजी के दामों का बढ़ना, लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है। जाहिर बात है कि इस वृद्धि से पहले ही महंगाई से जूझते लोगों का बजट और गड़बड़ा जाएगा। निस्संदेह, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि के बाद कुकिंग गैस के दामों की वृद्धि आम आदमी का बजट बिगाड़ने वाली है। फलतः लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है। वहीं आर्थिकी में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने की आशंका है। इस उथल-पुथल भरे वैश्विक परिदृश्य में कुछ कारक देश की अर्थव्यवस्था को संबल देने वाले भी हैं। देश में घरेलू मांग मजबूत है, संरचनात्मक विकास में निवेश जारी है। वहीं तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था हमारी ताकत भी है। जिससे हम एक सीमा तक वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हमारे आयात बिलों पर दबाव बढ़ा रही हैं। जिसका प्रभाव रुपये पर भी बढ़ते दबाव के रूप में सामने आया है। हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों को लुभाने के लिये केंद्रीय बैंक प्रयासरत है, लेकिन बाजार के पटरी पर आने में कुछ वक्त अवश्य लगेगा। आरबीआई का विश्वास है कि निवेश नियमों में ढील से पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय बैंक की प्राथमिकताओं में आर्थिक स्थिरता कायम करना, रुपये को संबल देना और देश की वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाये रखना भी है। बैंक की कोशिश है कि विकास को प्रभावित किए बिना ही आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास हो। निस्संदेह, नीति-नियंताओं के सामने आर्थिक विकास को गति देने के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिये दोनों में संतुलन बनाने की जरूरत है। हम विकास और रोजगार को संरक्षण देते हुए महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करें।

महिलाओं को ज्यादा झुलसाती है गर्मी की तपिश

क्षमा शर्मा

बहुत ज्यादा गर्मी महिलाओं की सामाजिक दुनिया को बदल देती है। हीटवेव के दौरान कई उष्णकटिबंधीय जगहों पर औरतें घर के अंदर रहती हैं, जिससे उनके सामाजिक संपर्क कम हो जाते हैं। बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल में तेज गर्मी को...बहुत ज्यादा गर्मी महिलाओं की सामाजिक दुनिया को बदल देती है। हीटवेव के दौरान कई उष्णकटिबंधीय जगहों पर औरतें घर के अंदर रहती हैं, जिससे उनके सामाजिक संपर्क कम हो जाते हैं। बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल में तेज गर्मी को बाल विवाह में बढ़ोतरी से जोड़ा गया है।भीषण गर्मी आज एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। दुनियाभर में हर साल लगभग 490,000 लोग गर्मी से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये आंकड़े महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी पर गर्मी के खतरनाक असर को नहीं दर्शाते। एक नए अध्ययन ने एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के उदाहरणों के हवाले से बताया है कि महिलाओं को गर्मी के हालात में सबसे ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जलवायु संबंधी नीतियों में उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है।

एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के कई हिस्सों में महिलाएं घर की मुख्य देखभाल करने वाली होती हैं। वे अक्सर पुरुषों के मुकाबले घर के अंदर ज्यादा समय बिताती हैं। उन्हें कम हवादार घरों में बिना इंसुलेशन या कूलिंग के रहना पड़ता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव होता है। इससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा गर्मी महिलाओं की सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है।काम की जगहों पर लिंग के आधार पर भेदभाव भी गर्मी के संपर्क को प्रभावित करता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अनौपचारिक काम की जगहों पर साफ-सफाई की कमी महिलाओं को बहुत ज्यादा गर्मी के दौरान खास तौर पर परेशान करती है। कुछ महिलाएं गंदे टॉयलेट इस्तेमाल करने से बचने के लिए कम पानी पीती हैं, जिससे उनमें डिहाइड्रेशन और सेहत से जुड़ी और दूसरी समस्याएं उत्पन हो जाती हैं। ये छोटी-मोटी परेशानियां नहीं हैं। ये सब मिलकर महिलाओं के गर्मी के संपर्क में निरंतर इजाफा करती हैं।बहुत ज्यादा गर्मी महिलाओं की सामाजिक दुनिया को बदल देती है। हीटवेव के दौरान कई उष्णकटिबंधीय जगहों पर औरतें घर के अंदर रहती हैं, जिससे उनके सामाजिक संपर्क कम हो जाते हैं। बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल में तेज गर्मी को बाल विवाह में बढ़ोतरी से जोड़ा गया है, क्योंकि मुश्किल में फंसे परिवार पैसे का तनाव कम करने और घर का खर्च कम करने के लिए अपनी बेटियों को शादी के लिए मजबूर करते हैं।एक अन्य अध्ययन के अनुसार दुनिया के कई हिस्सों में परिवार ऐसे घरों में रहते हैं जो गर्मी को अंदर रोककर रखते हैं, जहां बिजली की भरोसेमंद सुविधा नहीं है और साफ पानी की उपलब्धता सीमित है। बहुत से लोग आज भी चिलचिलाती धूप में बाहर काम करते हैं। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, इस तरह के हालात सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं।'नेचर सस्टेनेबिलिटी' में छपी एक नई स्टडी में बताया गया है कि दुनिया में अरबों लोग 'कूलिंग पॉवर्टी' (ठंडक की कमी) का सामना कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि दो अरब से ज्यादा लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसे वे कूलिंग पॉवर्टी कहते हैं। यानी वे खतरनाक गर्मी का सामना करते हैं और उनके पास ठंडक पाने के सुरक्षित या सस्ते तरीके नहीं होते।ये नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में इन गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इतनी ज्यादा गर्मी ये जरूरी सवाल खड़े करती है कि सबसे ज्यादा खतरे में कौन है और उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि इन लोगों को बस एक एयर कंडीशनर की जरूरत है। शोधकर्ता इस सोच को बदलना चाहते हैं। यूरो-मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज के वैज्ञानिक जियाकोमो फाल्चेटा ने कहा, कूलिंग पॉवर्टी का मतलब ऐसे हालात से है जहां लोगों को ताप सुरक्षा नहीं मिल पाती और इसकी वजह सिर्फ यह नहीं है कि उनके पास एयर कंडीशनर नहीं है।वैसे भी, एयर कंडीशनर बांटने से कोई लाभ नहीं होगा। वे बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं और कमजोर पावर ग्रिड पर बोझ डालते हैं।

हम इस संकट से निपटने के लिए सिर्फ एयर कंडीशनर का सहारा नहीं ले सकते। गरीबी गर्मी के असर को और बढ़ा देती है। स्टडी से पता चलता है कि गर्मी गरीबी, खराब घरों और कमजोर सार्वजनिक सेवाओं के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाती है। पहला खतरा तो घर ही है। कमज़ोर बनावट वाला घर आपको गर्मी से नहीं बचाता; बल्कि वह गर्मी को अंदर ही रोककर रखता है।शहरों में रहने वाले लाखों गरीब लोग टिन या एस्बेस्टस की छतों के नीचे रहते हैं, जिससे घर के अंदर का तापमान बाहर की हवा के मुकाबले पांच डिग्री तक ज्यादा हो सकता है। जब बिजली बार-बार जाती है और पानी सुरक्षित नहीं होता, तो पर्याप्त पानी पीना और शरीर को ठंडा रखना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा खतरा सेहत से जुड़ा है। जब भीषण गर्मी शरीर की सहनशक्ति से बाहर हो जाती है,तो जान बचाने के लिए अक्सर तुरंत मदद की जरूरत होती है।जिन देशों में क्लिनिक कम हैं या दूर हैं, वहां गर्मी से होने वाली बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। तीसरा खतरा काम से जुड़ा है।

राजनीतिक रुझान में दिखे बदलाव के संकेत

हालिया स्थानीय निकाय चुनावों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति का मूड बदल दिया है। भाजपा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। नतीजों ने सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर कांग्रेस की खामियां उजागर की हैं। बेशक 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीति में सरगर्मी बढ़ेगी।हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगर निगम और जिला परिषद चुनावों ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी है। इन चुनाव परिणामों की शुरुआत में केवल स्थानीय निकायों तक सीमित माना जा रहा था।

लेकिन परिणाम आने के बाद जाहिर हुआ कि जनता ने इन्हें सरकार के कार्य प्रदर्शन और राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा के रूप में देखा। भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक बढ़त ने सत्तासीन कांग्रेस सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष राजनीतिक चुनौतियां समय से पहले गहराती दिखाई देने लगी हैं।राज्य कांग्रेस सरकार का कार्यकाल अभी बाकी है लेकिन चुनावी परिणामों ने संकेत दिया कि जनता के एक वर्ग में धीरे-धीरे असंतोष पैदा हो रहा है। भाजपा ने इन नतीजों को सरकार के खिलाफ उभरते जनमत के रूप में पेश किया। यह संदेश देने की कोशिश की कि राज्य की राजनीतिक हवा बदलनी शुरू हो गई है।जिला परिषद चुनावों के परिणाम भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बनकर उभरे। कुल 253 सीटों में से 143 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी ने स्पष्ट बढ़त हासिल की, जबकि कांग्रेस 59 सीटों तक सीमित रह गई। यह अंतर केवल चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। भाजपा अब दावा करने लगी है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांवों तक फैल रही है।बिलासपुर में भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के गृह जिले में पार्टी ने जिला परिषद की सभी सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया कर दिया। इस जीत ने नड्डा के प्रभाव को फिर दर्शाया है। राज्य में अब भविष्य की राजनीति को लेकर नई चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।हमीरपुर के परिणामों ने भी कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा ने प्रभावी प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को करीब हाशिये पर पहुंचा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां सक्रिय रहे जो भाजपा का माहौल बनाने में मददगार रहा। सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस संगठन

जमीनी स्तर पर अपेक्षित मजबूती नहीं दिखा सका।साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आक्रामक चुनावी अभियान के दौरान कई बड़ी गारंटियां दी थीं। महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर किए गए वादों ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब विपक्ष इन्हीं गारंटियों को सरकार की बड़ी राजनीतिक कमजोरी में बदलने की कोशिश कर रहा है।भाजपा ने पूरे चुनाव प्रचार में यह नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया कि कांग्रेस अपने अधिकांश वादे पूरा करने में विफल रही। स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ बेरोजगारी, प्रशासनिक सुस्ती और विकास कार्यों में देरी जैसे विषयों को विपक्ष ने प्रभावी ढंग से उठाया। कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं और फैसलों का राजनीतिक लाभ जनता तक पहुंचाने में कमजोर दिखाई दी।सरकार की ओर से कई कल्याणकारी कदमों की घोषणा जरूर हुई, लेकिन राजनीतिक संवाद की कमी के कारण उनका प्रभाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा। यही वजह रही कि भाजपा जनता में यह धारणा बनाने में सफल होती दिखी कि सरकार और लोगों के बीच दूरी बढ़ रही है।साल 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा संगठन में निराशा का माहौल था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों ने पार्टी को नई ऊर्जा दे दी है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनावी रणनीति को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखा। भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति के बजाय प्रशासनिक कमजोरी, अधूरी घोषणाओं और जन असंतोष को हथियार बनाया।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बूथ स्तर के नेटवर्क ने भी भाजपा की चुनावी तैयारी को मजबूती दी। पार्टी अब यह मानने लगी है कि यदि यही राजनीतिक माहौल बना रहा तो सत्ता विरोधी भावना 2027 से पहले ही अधिक तीव्र हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भाजपा अभी भी राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी मान रही है।मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए यह स्थिति केवल राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि प्रशासनिक परीक्षा भी बनती जा रही है। यदि कांग्रेस इन नतीजों को केवल स्थानीय चुनावों तक सीमित मानकर नजरअंदाज करती है,

तो सरकार और जनता के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो सकती है। कांग्रेस नेतृत्व को अब तेजी से संगठनात्मक तालमेल मजबूत करना होगा। साथ ही चुनावी गारंटियों के क्रियान्वयन, युवाओं के बीच भरोसा बहाल करने और मध्य वर्ग की नाराजगी कम करने की दिशा में प्रभावी राजनीतिक संदेश देना होगा।

आने वाले महीनों में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह प्रशासनिक फैसलों को राजनीतिक समर्थन में कैसे बदले।2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय चुनावों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति का मूड बदल दिया है।

भाजपा आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राज्य की राजनीति आने वाले समय में और अधिक तीखी तथा प्रतिस्पर्धी होने के संकेत दे रही है।

तलाक का दबाव, मारपीट और जिंदा जलाने की कोशिश!

एक ही परिवार के दो पक्ष आमने-सामने

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में पारिवारिक विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया। एक महिला ने अपने पति, सास समेत छह लोगों पर तलाक देने का दबाव बनाने, मारपीट करने और उसे तथा उसके बच्चों को जिंदा जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी महिला पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच में जुटी है।

चंद्रपुरा निवासी किरन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे उसके पति बलवीर, सास सुरजा देवी और अन्य परिजन घर पहुंचे। आरोप है कि सभी ने उस पर स्टाम्प पेपर पर तलाक देने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई। महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसे और उसके तीन नाबालिग बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता के अनुसार, विवाद के दौरान उसके कपड़ों में आग लगाने का भी प्रयास किया गया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उसकी और बच्चों की जान बच सकी। घटना की सूचना

- महिला ने पति, सास समेत छह लोगों पर लगाया गंभीर आरोप
- ससुर ने बहू पर हमले की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की

तत्काल डायल-112 पर दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से चले गए।

महिला ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए आशंका जताई है कि भविष्य में उसके और बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है।उधर, मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। महिला के ससुर रामसेवक ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले हुए विवाद में उन्हें लाठी-डंडों से पीटा गया था। उनका कहना है कि दो जून को वह घायल अवस्था में थाने पहुंचे थे और बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।हालांकि किरन का कहना है कि उस दिन उसकी सास ने उस पर डंडे से हमला किया था।

बचाव के दौरान डंडा पीछे खड़े ससुर को लग गया, जिसके बाद उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है।उधर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

22 दिन से बिजली ठप

ट्रांसफार्मर न बदले जाने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

- जिला पंचायत सदस्य के साथ बिजलीघर पहुंचे ग्रामीण, जल्द समाधान की मांग
- अवर अभियंता ने जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने का दिया आश्वासन

शिवराजपुर/बिल्हौर (कानपुर)। जवासी बगिया गांव में पिछले 22 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लगातार अंधेरे में रह रहे ग्रामीण सोमवार को जिला पंचायत सदस्य कार्तिकेय शुक्ला के नेतृत्व में स्थानीय विद्युत उपकेंद्र पहुंच गए और अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव का ट्रांसफार्मर कई दिन पहले खराब हो गया था, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था प्रभावित है। कई बार शिकायत करने और विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। इससे पहले भी ग्रामीण बिजलीघर पहुंचकर विरोध जता चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बिजली न होने से ग्रामीणों का दैनिक जीवन प्रभावित हो गया है। कूलर, पंखे और अन्य विद्युत उपकरण बंद पड़े हैं, जबकि लगातार कटौती के कारण इनवर्टर भी जवाब दे चुके हैं। पेयजल व्यवस्था पर भी असर पड़ा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

जिला पंचायत सदस्य कार्तिकेय शुक्ला ने कहा कि लंबे समय से ट्रांसफार्मर न बदले जाने से ग्रामीणों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना

करना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं विद्युत विभाग के अवर अभियंता विमलेश दुबे ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया जारी है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जल्द नया ट्रांसफार्मर स्थापित कर बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जाएगा।

वारंटी को घर से उठाया, पेशी के बाद जेल भेजा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। न्यायालय से जारी वारंटों के अनुपालन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ककवन पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार सरिगवा गांव निवासी रामप्रकाश के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी था। रविवार को थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसके घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी

करने वाली टीम में नदिहा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक भारतेन्द्र प्रताप, उपनिरीक्षक जितेंद्र भाटी, हेड कांस्टेबल जसवीर सिंह और कांस्टेबल अनुज शामिल रहे। अभियान के तहत पुलिस अन्य वांछितों और वारंटियों की भी तलाश कर रही है।

पिकअप-बाइक भिड़ंत में चार युवक गंभीर, चालक फरार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। ककवन थाना क्षेत्र में लखनऊ-इटावा हाईवे पर सोमवार को तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले ककवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार औरतरपुर ग्रामसभा के मेवाड़ा गांव निवासी दीपक, शिवम, अनुभव और रौनक एक बाइक से ककवन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान डम्मरनिवादा गांव के सामने बिल्हौर की दिशा में जा रही तेज रफ्तार पिकअप से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल भेज दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त पिकअप को कब्जे में ले लिया। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। ककवन थाना प्रभारी जितेंद्र राजपूत ने बताया कि वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तहसील की बदहाल व्यवस्था पर भड़के अधिवक्ता, नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील परिसर में व्याप्त विभिन्न प्रशासनिक और राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन कर नारेबाजी की और उपजिलाधिकारी मनीष कुमार को ज्ञापन सौंपा। लॉयर्स एवं बार एसोसिएशन बिल्हौर के अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील में लंबित मामलों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिससे आम जनता और वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में मांग की गई कि लेखपालों की पूर्व व्यवस्था के अनुसार मंगलवार और शुक्रवार को तहसील परिसर में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। धारा 76, धारा 116 तथा धारा 32/38 से संबंधित पत्रावलियों का सरलीकरण करते हुए समयबद्ध निस्तारण कराया जाए। विभिन्न न्यायालयों से पारित आदेशों को

- लेखपालों की अनुपस्थिति, लंबित दाखिल-खारिज और वरासत मामलों पर जताई नाराजगी
- पुराने आश्वासन के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी

ऑनलाइन अपलोड करने में आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाए।

अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन आवेदन की गई वरासत संबंधी पत्रावलियों को कई बार बिना स्थलीय जांच के निरस्त कर दिया जाता है तथा अंश सुधार के मामलों में भी गंभीर उदासीनता बरती जा रही है।

कई गांवों में अंश निर्धारण न होने के कारण आदेशों का निफाज नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों की फार्मर रजिस्ट्री भी प्रभावित हो रही है।ज्ञापन में बैनामा, वसीयत, वरासत एवं दाखिल-खारिज के अविवादित मामलों के लिए

विशेष अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की गई। साथ ही राजस्व अभिलेखागार से मांगी गई पत्रावलियों के महीनों तक न पहुंचने पर नाराजगी जताते हुए इसके लिए सुदृढ़ व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।

अधिवक्ताओं ने कहा कि इससे पूर्व भी संगठन द्वारा तहसील की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिस पर 15 दिन में समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की।

लापता नाबालिगों पर हाईकोर्ट सख्त

पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब

राजधानी में 81 लड़कियों के अपहरण और गुमशुदगी के मामले, 15 अब भी लापता

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में नाबालिग लड़कियों के लगातार गायब होने और अपहरण के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गंभीर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया है। न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर से इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण तलब किया है और डीसीपी पूर्वी को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के उन सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों के साथ अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, जिनके पास ऐसे मामले लंबित हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने यह आदेश 12 वर्षीय एक लापता बच्ची के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में बताया गया था कि बच्ची चार महीने से लापता थी और पुलिस की निष्क्रियता के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और सख्त रुख के बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद कर अदालत में पेश किया। अदालत में बच्ची ने अपने पिता के साथ जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसे पिता के सुपुर्द कर दिया गया।

डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र के नौ थानों में कुल 81 लड़कियों के अपहरण अथवा बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले दर्ज हैं।

इनमें अधिकांश नाबालिग हैं। अब तक 66 लड़कियों को बरामद कर लिया गया है, जबकि 15 लड़कियां अभी भी लापता हैं। इस पर न्यायालय ने डीसीपी को सभी मामलों की व्यक्तिगत निगरानी करने और तीन दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह मामला नाबालिग बच्चियों के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा है,

इसलिए किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने संबंधित थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जों और विवेचकों को सचेत करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश भी दिए हैं।

साथ ही ऐसे मामलों का भी पता लगाने को कहा गया है जिनकी शिकायत अभी तक पुलिस के पास दर्ज नहीं कराई गई है।

इसी दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में हुई वकीलों की हड़ताल और न्यायिक कार्य बहिष्कार पर भी कड़ा रुख अपनाया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की अवकाशकालीन पीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत तीन अधिवक्ताओं को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

न्यायालय ने यह भी पूछा है कि उनके आचरण की शिकायत उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को क्यों न भेजी जाए।

यह आदेश उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने के आदेश के विरोध में वकीलों द्वारा किए गए आंदोलन और कार्य बहिष्कार का मुद्दा उठाया गया था। अदालत ने मामले में जिला जज से भी रिपोर्ट तलब की थी।

निर्माणाधीन 49वीं वाहिनी पीएसी का डीजी पीएसी ने किया निरीक्षण

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरे करने के दिए निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक पीएसी आलोक सिंह ने रविवार को ग्राम लुकसर, कासना स्थित निर्माणाधीन 49वीं वाहिनी पीएसी परिसर का भ्रमण एवं निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके कार्यों की प्रगति का गहन जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सेनानायक 49वीं वाहिनी रामनयन सिंह तथा लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। डीजी पीएसी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों तथा सुविधाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।कार्यक्रम के दौरान डीजी ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद आयोजित सैनिक सम्मेलन में उन्होंने पीएसी कार्मिकों को आधुनिक तकनीकों और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए अपनी व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बदलते समय में सुरक्षा बलों के लिए तकनीकी दक्षता और अनुशासन बेहद आवश्यक है।इस अवसर पर बैंड कर्मियों द्वारा आकर्षक एवं उत्कृष्ट बैंड वादन की प्रस्तुति दी गई, जिसकी उपस्थित अधिकारियों ने सराहना की। निरीक्षण के दौरान डीआईजी मेरठ अनुभाग कल्पना सक्सेना, सेनानायक रामनयन सिंह, सहायक सेनानायक अनिल कुमार, सहायक सेनानायक (यूपीएसएसएफ) राजीव यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही लोक निर्माण विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता मोहम्मद आरिफ, सहायक अभियंता एहतशाम अनवर, त्रुषाल सिंह एवं उनकी टीम भी उपस्थित रही।

डीएम-एसपी की कड़ी निगरानी में पुलिस भर्ती परीक्षा सम्पन्न

» जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज तथा दयानंद वैदिक कॉलेज सहित कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

जालौन। पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा-2025 के दूसरे दिन जनपद में सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क रहा। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज तथा दयानंद वैदिक कॉलेज सहित कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता तथा परीक्षा संचालन की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा।

अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थापकों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान पत्र, बायोमेट्रिक सत्यापन और गहन तलाशी के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

जिले के नौ परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित परीक्षा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। डीएम और एसपी स्वयं चिलचिलाती धूप में लगातार भ्रमणशील रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे तथा पुलिस बल को पूरी सतर्कता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए।

प्रशासन की कड़ी निगरानी और प्रभावी व्यवस्थाओं के चलते सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान नकल अथवा किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी की कोई शिकायत सामने नहीं आई। अधिकारियों ने कहा कि भर्ती परीक्षा की शुचिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए जिले भर में लगातार निगरानी रखी जा रही है।

सलारपुर गौशाला की बदहाल व्यवस्था पर विहिप का फूटा गुस्सा

मृत गौवंश को कुत्तों द्वारा नोचने का आरोप, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अमरौधा विकासखंड की नगवा ग्राम पंचायत स्थित सलारपुर अस्थायी गौशाला एक बार फिर अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) गौ रक्षा विभाग ने गौशाला में संरक्षित गौवंश की देखभाल में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संगठन का दावा है कि गौशाला परिसर में मृत पड़ी गौमाताओं के शवों को समय पर हटाया नहीं गया, जिसके चलते आवारा कुत्ते उन्हें नोचते रहे और हड्डियां इधर-उधर ले जाते दिखाई दिए।

गौशाला के अंदर हड्डी लेते जाते आवारा कुत्ते

विहिप गौ रक्षा विभाग के जिला गौरक्षा प्रमुख मनन बजरंगी ने बताया कि सलारपुर गौशाला में करीब 41 गौवंश संरक्षित हैं। उन्हें स्थानीय लोगों के माध्यम से सूचना मिली कि गौशाला परिसर में दो गौमाताएं मृत अवस्था में पड़ी हैं।

मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने पर अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई। उनका आरोप है कि मृत गौवंश का नियमानुसार और समय पर अंतिम संस्कार नहीं कराया गया, जिससे न केवल गौशाला की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए बल्कि क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भी आहत हुई हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि गौशाला के सचिव अवधेश तथा ग्राम प्रधान की ओर से गौवंश की देखरेख में घोर लापरवाही बरती जा रही है। गौशाला में नियुक्त केयरटेकर के घर चले जाने से परिसर खुला पड़ा था और निगरानी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। इससे गौवंश की सुरक्षा और देखभाल पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।विहिप पदाधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी खंड विकास अधिकारी अमरौधा विश्राम सिंह को देते हुए तत्काल जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

संगठन का कहना है कि सरकार गौवंश संरक्षण के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की अनदेखी से गौशालाओं का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है।

पदाधिकारियों का कहना है कि गौशालाएं गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाई गई हैं, लेकिन लापरवाही के कारण यदि वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो यह बेहद चिंताजनक है।

घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और ग्रामीण भी गौशाला की व्यवस्थाओं में सुधार तथा नियमित निगरानी की

मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

साहब! कागजों से नहीं प्यास बुझती गांव वालों को पानी भी दिलाइए

मल्हपुर को कनेक्शन मिलने के बाद बढ़ी परेशानी, ग्रामीणों ने की स्थायी समाधान की मांग

» स्वराज इंडिया संवाददाता

रसूलाबाद(कानपुर देहात)। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर जल योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कई गांवों में योजना का लाभ अपेक्षित रूप से नहीं मिल पा रहा है। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के बारापुर गांव में जलापूर्ति प्रभावित होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जिलाधिकारी ने जलापूर्ति संबंधी शिकायतों पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है।ग्राम पंचायत बर्रा-ठर्रा के मजरा पहाड़पुर में स्थापित पानी की टंकी से बर्रा-ठर्रा, देवहरेपुर, कनपटियापुर और बारापुर गांवों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना शुरू होने के समय पानी की आपूर्ति नियमित और पर्याप्त मात्रा में हो रही थी, लेकिन बाद में इसी लाइन से मल्हपुर गांव को भी जोड़ दिए जाने के बाद बारापुर में पानी की समस्या शुरू हो गई।

ग्रामीण अजय कुमार, श्रीकांत कुमार, मनोज कुमार, कमलेश यादव, अवधेश कुमार, बृजमोहन सिंह, कुलदीप कुमार और सोनू कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि गांव के कुछ हिस्सों में बहुत कम दबाव से पानी पहुंचता है, जबकि दो मोहल्लों में पानी बिल्कुल नहीं आता। कई बार एक-दो दिन में केवल एक-दो बाल्टी पानी ही मिल पाता है, जिससे लोगों को पीने के पानी और घरेलू कार्यों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन हर बार केवल अस्थायी समाधान ही किया गया। शिकायत के बाद एक-दो दिन तक पानी की आपूर्ति ठीक रहती है, फिर स्थिति पहले जैसी हो जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि मल्हपुर गांव की ओर अधिक पानी जाने के कारण बारापुर में पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

भीषण गर्मी के बीच जल संकट ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। महिलाओं को दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि विभाग तत्काल तकनीकी जांच कराकर समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करे, ताकि सभी मोहल्लों में नियमित और पर्याप्त जलापूर्ति हो सके।

क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी

इस संबंध में जल निगम के अधिशासी अभियंता टीआर. कटारिया ने बताया कि बारापुर मजरे में पानी न पहुंचने की शिकायत प्राप्त हुई है। विभागीय टीम से जांच कराई जाएगी और समस्या का शीघ्र समाधान कराकर जलापूर्ति सुचारु कराई जाएगी

हादसों में छह घायल, करंट से झुलसा अधेड़

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों और एक विद्युत दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। देवराहट थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार महेश और राजेश, निवासी राजपुर, घायल हो गए। दोनों युवक बाइक से प्रेमपुर गांव जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखरायां पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया। वहीं भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के समीप अज्ञात वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मुकेश, विजय और सुरेश, निवासी माधौगढ़ (जालौन), घायल हो गए। तीनों कानपुर की ओर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें उपचार के लिए अकबरपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया।

बेटी-दामाद पर जमीन हड़पने, बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप

एसपी के यहां से शिकायत पत्र देकर वापिस लौटती पीड़ित बुजुर्ग महिला

» बुजुर्ग महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद की एक 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी, दामाद और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर जमीन हड़पने, बंधक बनाकर प्रताड़ित करने तथा बैंक खाते से रुपये निकालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले में मुकदमा दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

गजनेर थाना क्षेत्र की भदेसा गांव निवासी अनुसुइया उर्फ सईया देवी ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वर्ष 2023 में उनकी पुत्री ममता देवी उन्हें अपने साथ गोहाना स्थित आवास पर ले गई थी। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि शुरुआती दिनों में परिवार का व्यवहार सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद उन पर अपनी नकदी, कीमती सामान और कृषि भूमि बेटी के नाम करने का दबाव बनाया जाने लगा।

पीड़िता का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें घर में बंधक बनाकर रखा गया

और मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि 28 नवंबर 2023 को बेटी, दामाद तथा अन्य परिजनों ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, कट्टा दिखाकर भयभीत किया गया और जबरन तहसील ले जाकर उनकी कृषि भूमि बेटी ममता देवी के नाम दर्ज करा ली गई।

बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी उन्हें घर में नजरबंद रखा गया और किसी से संपर्क नहीं करने दिया गया। उनके अनुसार, उनके जेवरात भी कब्जे में ले लिए गए तथा बैंक खाते से लगभग 78,930 रुपये निकाल लिए गए।

पीड़िता ने बताया कि 20 दिसंबर 2023 को रिश्तेदारों की मदद से वह किसी तरह वहां से निकलकर अपने पैतृक घर पहुंच सकीं। इसके बाद उन्होंने राजस्व न्यायालय में भूमि पुनर्स्थापन के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया, जहां मामला विचाराधीन है।

अब अनुसुइया उर्फ सईया देवी ने पुलिस अधीक्षक से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर मुकदमा दर्ज करने, कथित रूप से हड़पी गई संपत्ति वापस दिलाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झींझक रेलवे स्टेशन पर चला सघन चेकिंग अभियान, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। कानपुर-दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित जनपद के प्रमुख रेलवे स्टेशन झींझक पर यात्रियों की सुरक्षा एवं रेलवे परिसरों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट घर तथा आने-जाने वाले मार्गों का गहन निरीक्षण किया गया।

जीआरपी चौकी प्रभारी झींझक अर्पित तिवारी एवं स्टेशन मास्टर प्रांशु तिवारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों एवं लावारिस सामान की सघन जांच की गई। अधिकारियों ने यात्रियों से सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे पुलिस अथवा स्टेशन प्रशासन को देने की अपील की।चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं का निरीक्षण करते हुए यात्रियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और रेलवे स्टेशन पर नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाए जाते रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके।रेलवे प्रशासन एवं जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई से स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है। यात्रियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए आवश्यक बताया।

भाजपा टिकट के लिए कृष्ण मुरारी दोहरे ने ठोकी दावेदारी

» रसूलाबाद सीट पर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी, विकास और जनसेवा को बनाया मुद्दा

» स्वराज इंडिया संवाददाता

रसूलाबाद (कानपुर देहात)। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। चुनावी तैयारियों के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवार अपनी सक्रियता बढ़ाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक कृष्ण मुरारी दोहरे ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर क्षेत्रीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है।

कृष्ण मुरारी दोहरे ने कहा कि उन्होंने अपने लंबे पुलिस एवं प्रशासनिक सेवा काल के दौरान जनता की समस्याओं को नजदीक से देखा और समझा है। सेवा के दौरान प्राप्त अनुभव को अब वह जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र के विकास में लगाना चाहते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि भाजपा नेतृत्व उन्हें रसूलाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाता है तो वह पार्टी की नीतियों और केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उनके पास स्पष्ट दृष्टिकोण और कार्ययोजना है।

दोहरे जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं, भाजपा पिछले कुछ चुनावों में उस वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने पर विशेष जोर देती रही है। यही वजह है कि उनकी सक्रियता और दावेदारी को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में टिकट को लेकर प्रतिस्पर्धा और तेज होगी तथा रसूलाबाद विधानसभा का चुनावी मुकाबला काफी रोचक और दिलचस्प बन सकता है।

महटोली ओवरब्रिज पर रोडवेज बस डंपर से टकराई, चालक-परिचालक समेत 15 घायल

चालक को नींद की झपकी आने के कारण बस का संतुलन बिगड़ गया था

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अमराहट थाना क्षेत्र के महटोली ओवरब्रिज पर दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी रोडवेज बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में चालक, परिचालक समेत 15 यात्री घायल हो गए। घायलों में एक वृद्ध महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।जानकारी के अनुसार हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि बस चालक को नींद की झपकी आने के कारण बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने चल रहे डंपर से जा टकराई।

टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।सूचना मिलते ही अमराहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा भेजा गया। बस में करीब 45 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 लोग घायल हुए। घायलों में बस चालक मजीद खान निवासी खेरिया मोड़, आगरा, परिचालक अनिल कुमार निवासी खेरागढ़, आगरा, सुधर्मा (78) पत्नी स्व. महावीर निवासी अंबिकापुर, शुक्लागंज (उन्नाव), पुष्पा, अर्चना कुमारी, भरत ठाकुर, आदर्श ठाकुर, वैभव ठाकुर, लालजी, अनूपा, सर्वेश, बुधराम कुमार, रामकरण सिंह, सुनील तथा ऋषभ शामिल हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में सभी घायलों का उपचार किया गया। अन्य घायलों को उपचार के बाद उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की सहायता से राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाकर महटोली चेक पोस्ट पर सुरक्षित खड़ा करा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

निराला नगर प्लेयर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

» स्वराज इंडिया संवाददाता

रसूलाबाद (कानपुर देहात)। कस्बे के निराला नगर वार्ड में आयोजित निराला नगर प्लेयर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ नगर पंचायत रसूलाबाद के अध्यक्ष देवशरण कमल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलकूद से शरीर स्वस्थ एवं चुस्त-दुरुस्त रहता है।

खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना का विकास करते हैं तथा आपसी भाईचारा भी बढ़ाते हैं।उद्घाटन के बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रतनपुर और निराला नगर की टीमों के बीच खेला गया।

रोमांचक मुकाबले में रतनपुर की टीम ने जीत हासिल की। टूर्नामेंट आयोजकों ने मुख्य अतिथि का फूलमालाओं से स्वागत किया। देवशरण कमल ने कहा कि क्रिकेट आज युवाओं के लिए करियर का भी एक अच्छा माध्यम बन चुका है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने और बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। विवेक पाल, आशीष पाल, मोहित, शिवा, सचिन, विजय, विशाल, सत्यम, जय सिंह, छोटे, सचिन आदि रहे।

मजदूरों ने भट्ठा मालिक व मुनीम पर मजदूरी न देने का लगाया आरोप

शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक ईंट भट्ठे पर कार्यरत मजदूरों ने भट्ठा मालिक और मुनीम पर मजदूरी का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जिला बांदा के थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम भगू का पुरवा निवासी विजय पुत्र स्वर्गीय गिरधारी ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि भट्ठा मालिक के कहने पर मुनीम करीब 50 मजदूरों को बांदा जिले के नगनिधि गांव से काम कराने के लिए लेकर आया था। आरोप है कि काम के दौरान मजदूरों को केवल थोड़ी-थोड़ी खुराकी दी जाती रही।

मजदूरों का कहना है कि 29 मई को पथाई का कार्य बंद होने के बाद उनकी करीब 7 लाख 50 हजार रुपये की मजदूरी बनती है। भुगतान मांगने पर भट्ठा मालिक ने गांव पहुंचकर रुपये देने की बात कही, लेकिन बाद में टालमटोल करने लगा। आरोप है कि मजदूरी की मांग करने पर भट्ठा मालिक और मुनीम ने उन्हें धमकाते हुए वहां से चले जाने को कहा। मजदूरों के अनुसार अधिकांश श्रमिक अभी भी भट्ठे पर ही मौजूद हैं और उन्हें मजदूरी मिलने का इंतजार है। मामले में उपनिरीक्षक अभिनेष कुमार ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यूपी में मजदूरों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, 125 दिन रोजगार की गारंटी

मनरेगा की जगह लागू होगी वीबी जीरामजी योजना, जुलाई से शुरू करने की तैयारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। योगी सरकार केंद्र सरकार की विकसित भारत-जी रामजी (वीबी जीरामजी) योजना को प्रदेश में लागू करने जा रही है। ग्राम्य विकास विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे मंजूरी के लिए योगी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। सरकार का लक्ष्य जुलाई से योजना को पूरी तरह लागू करना है।

नई व्यवस्था के तहत खेती-किसानी से जुड़े मजदूरों को फसलों की बुवाई और कटाई के दौरान काम मिलने के बावजूद, खाली समय में बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया जाएगा।

योजना का उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को सालभर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर वीबी जीरामजी योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में भी नई योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें वर्तमान मनरेगा मजदूरों को शामिल किया जाएगा, साथ ही नए पात्र श्रमिकों का भी पंजीकरण किया जाएगा।

योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। खेती के व्यस्त सीजन को छोड़कर शेष अवधि में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बुवाई और कटाई के दौरान लगभग 60 दिन का 'नो वर्क' समय माना जाएगा, जबकि बाकी अवधि में रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा और यह भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।

योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सत्यापन व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। मजदूरों से फीडबैक लेकर गड़बड़ियों पर रोक लगाने और खामियों को दूर करने की व्यवस्था की जाएगी। जल संरक्षण, कृषि विकास, भूजल स्तर सुधार, सड़क निर्माण और ग्रामीण संपर्क मार्गों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रदेश में वर्तमान समय में मनरेगा के तहत 2.43 करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं। इनमें 1.82 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सक्रिय मजदूरों की संख्या 1.21 करोड़ तथा सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या 86.15 लाख है। नई योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आर्थिक सहायता का लाभ मिलने की उम्मीद है।

सिपाही भर्ती परीक्षा देने आई युवतियों से दुष्कर्म का प्रयास मुठभेड़ में दबोचा गया आरोपी

» चारबाग से ऑटो में बैठीं अभ्यर्थियों को सुनसान इलाके में ले गया चालक, पुलिस कार्रवाई में पैर में लगी गोली

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा देने राजधानी लखनऊ पहुंचीं युवतियों के साथ दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक हसीब को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।जानकारी के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों ने चारबाग क्षेत्र से परीक्षा केंद्र जाने के लिए ऑटो किया था। आरोप है कि चालक हसीब उन्हें तय मार्ग से हटाकर सुनसान इलाके की ओर ले गया। वहां उसने युवतियों के साथ जबरदस्ती और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने अभ्यर्थियों के साथ मारपीट भी की।पीड़ित युवतियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू की। देर रात पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हसीब के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवतियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की गहन जांच की जा रही है।

हनुमान मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या सिर कुचलकर उतारा मौत के घाट

» मंदिर परिसर में रक्तरंजित मिला शव, पास से ईंट-पत्थर और लोहे की रॉड बरामद

घटनास्थल पर जांच करती फोरेंसिक टीम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हाथरस जिले में सहपऊ कस्बे स्थित हनुमान टीला मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सोमवार सुबह मंदिर परिसर में पुजारी का शव रक्तरंजित अवस्था में तख्त के नीचे पड़ा मिला। उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी।मृतक की पहचान 51 वर्षीय दिलीप उर्फ चंदू लाला निवासी नगला सुखराम, थाना सहपऊ के रूप में हुई है। वह पिछले करीब आठ महीनों से हनुमान टीला मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा-पूजा कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रविवार देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके सिर पर भारी वस्तु से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटनास्थल से ईंट-पत्थर और लोहे की रॉड बरामद हुई है, जिन्हें हत्या में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के बड़े भाई प्रबल प्रताप ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है।घटना की खबर फैलते ही मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का दावा है कि कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जो हत्यारों तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, दिव्यांग और अविवाहित पुजारी दिलीप मंदिर परिसर में नशा करने वालों के आने-जाने का विरोध करते थे। उन्होंने पिछले कई महीनों से मंदिर में नशेड़ियों के प्रवेश पर सख्ती कर रखी थी। क्षेत्र में चर्चा है कि यही सख्ती उनकी हत्या की वजह बन सकती है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और जल्द घटना के खुलासे का दावा कर रही है।

इकलौते बेटे को खोकर बिखर गया परिवार, तेंदुआ अब भी पकड़ से दूर

» मां पुकारती रही शुभ शुभम्, लेकिन हमेशा के लिए खामोश हो गई आवाज

» दिनभर खेतों और झाड़ियों में चला सर्च ऑपरेशन, अफवाहों के बीच दहशत में इलाका

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

घटना स्थल पर कांबिंग करती वनविभाग की टीम

लखीमपुर खीरी। तहसील धौरहरा क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी सात वर्षीय मासूम शुभम यादव की जान लेने वाले तेंदुए की तलाश सोमवार को काफी देर तक जारी रही, लेकिन दिनभर चले अभियान के बाद भी वन विभाग और पुलिस के हाथ खाली रहे। खेतों, बागों और जंगल से सटे इलाकों में सघन कांबिंग की गई, मगर हमलावर तेंदुआ कहीं नजर नहीं आया। इससे ग्रामीणों में भय और बढ़ गया है।

तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने इलाके में तीन पिंजरे लगाए हैं। निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं और थर्मल ड्रोन की मदद भी ली गई, लेकिन देर शाम तक कोई ठोस सफलता नहीं मिल सकी। अधिकारियों के मुताबिक हर संभावित स्थान पर नजर रखी जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफवाहों का दौर भी चलता रहा। कहीं गन्ने के खेत में तेंदुआ दिखने की सूचना मिली तो कहीं केले के बाग में उसके छिपे होने का दावा किया गया। हर सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जांच में कोई भी सूचना सही नहीं निकली। दिनभर यही स्थिति बनी रही और अधिकारी लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ते रहे।

उधर, शुभम की मौत के बाद रायपुर और आसपास के गांवों में शोक और डर का माहौल है। ग्रामीण अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से बच रहे हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला। परिजनों ने घायल बच्चे को समय पर समुचित इलाज न मिलने का आरोप लगाया। इसी को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। बाद में क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी और अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ।

गौरतलब है कि दो माह पहले भी निघासन क्षेत्र में तेंदुए के हमले में एक मासूम की जान चली गई थी। ऐसे में रायपुर की घटना ने एक बार फिर वन्यजीवों की बढ़ती गतिविधियों और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल लोगों की निगाहें उस तेंदुए पर टिकी हैं, जिसकी तलाश में पूरा प्रशासन जुटा है, लेकिन जो अब तक पकड़ से बाहर है।

महर्षि आश्रम ट्रस्ट भूमि घोटाला: ईडी की जांच तेज, 1993 से अब तक की रजिस्ट्रियां खंगालीं

» 3.36 हेक्टेयर जमीन की कथित धोखाधड़ी में बड़े खुलासों के संकेत

» सब-रजिस्ट्रार से तीन घंटे पूछताछ, दो आरोपी पहले ही हो चुके गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

नोएडा। महर्षि आश्रम ट्रस्ट की जमीन बेचने से जुड़े बहुचर्चित भूमि घोटाले में ईडी ने अपनी जांच और तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने अब रजिस्ट्री विभाग से वर्ष 1993 से लेकर अब तक हुए सभी भूमि हस्तांतरण और बैनामों के दस्तावेज तलब किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, सेक्टर-110 स्थित महर्षि आश्रम से जुड़ी करीब 3.36 हेक्टेयर जमीन के फर्जीवाड़े और अवैध बिक्री के मामले में कई अहम दस्तावेज एजेंसी के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी अधिकारियों ने नोएडा के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से करीब तीन घंटे तक गहन पूछताछ की। इस दौरान जमीन के स्वामित्व, पुराने बैनामों, ट्रस्ट से जुड़े अभिलेखों और रजिस्ट्री प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल किए गए। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ट्रस्ट की भूमि किन परिस्थितियों में निजी हाथों तक पहुंची और क्या इसमें सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल थी। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि महर्षि आश्रम ट्रस्ट की जमीन पर वर्षों के दौरान कई निर्माण कार्य हुए और कुछ हिस्सों में बड़े स्तर पर आवासीय परियोजनाएं विकसित कर दी गईं। मामले में धन शोधन, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अवैध तरीके से जमीन बेचने के आरोपों की जांच की जा रही है। इस प्रकरण में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। जांच एजेंसी अब उन लोगों की भूमिका खंगाल रही है जिन्होंने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन के सौदों को वैध रूप देने का प्रयास किया। सूत्रों का दावा है कि आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारियों और बिल्डरों से पूछताछ हो सकती है।

सांसद अवधेश प्रसाद के पैतृक गांव की सूखी झील पर तीन करोड़ का श्रृंगार !

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या में विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, घाट सज रहे हैं और झीलों के सुंदरीकरण की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। लेकिन सोहावल ब्लॉक की सुरवारी झील को लेकर अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस झील में आज नाम मात्र का पानी है, उसी झील के सुंदरीकरण पर लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह झील समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के पैतृक गांव सुरवारी में स्थित है। ऐसे में परियोजना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

» सुरवारी झील में पानी नहीं, लेकिन सुंदरीकरण पर करोड़ों की बरसात

» क्या विकास की तस्वीर बन रही है या सरकारी धन के उपयोग पर उठेंगे सवाल?

पहले यह परियोजना करीब चार करोड़ रुपये की थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया के बाद इसकी लागत घटकर लगभग तीन करोड़ रुपये रह गई।

अयोध्या विकास प्राधिकरण यहां सीढ़ियां, घाट, तालाब और अन्य संरचनाओं का निर्माण करा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि बरसात शुरू होते ही झील में पर्याप्त पानी आ जाएगा और इसे स्थायी जल संरक्षण मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल–पहले पानी या पहले सुंदरीकरण?

स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि जिस झील में साल के अधिकांश समय पानी ही नहीं रहता, वहां करोड़ों रुपये का सुंदरीकरण कितनी प्राथमिकता वाला काम है? क्या पहले जल संरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में झील साल भर पानी से भरी रहेगी? यदि पानी नहीं रहा तो क्या करोड़ों रुपये की संरचनाएं केवल कंक्रीट का ढांचा बनकर रह जाएंगी?

चार लाख से तीन करोड़ तक का सफर

बताया जाता है कि कुछ वर्ष पहले इसी झील पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किए गए थे। अब वही झील तीन करोड़ रुपये की परियोजना के केंद्र में है। अधिकारियों का दावा है कि यहां पक्षियों के लिए कृत्रिम टापू बनाए जाएंगे, प्राकृतिक वातावरण विकसित होगा और झील का जलस्तर बनाए रखने के लिए विशेष डिजाइन तैयार की गई है। अब जनता जानना चाहती है की विकास कार्यों पर किसी को आपत्ति नहीं है।

लेकिन जब करोड़ों रुपये सार्वजनिक धन के रूप में खर्च होते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या परियोजना का तकनीकी सर्वे सार्वजनिक किया जाएगा? झील में बारहमासी पानी बनाए रखने की क्या व्यवस्था है? क्या इस खर्च का सामाजिक और पर्यावरणीय आकलन हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल क्या यह परियोजना वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के लिए है या सिर्फ कंक्रीट आधारित सुंदरीकरण का एक और उदाहरण? अयोध्या में विकास जरूरी है,

लेकिन विकास की सफलता का पैमाना केवल खर्च की गई राशि नहीं, बल्कि उसका वास्तविक परिणाम होता है। सुरवारी झील पर खर्च हो रहे करोड़ों रुपये अब जनता की निगाह में हैं।

आने वाले मानसून के साथ यह भी साफ हो जाएगा कि यहां पानी ज्यादा टिकता है या सवाल।

आरटीओ में कमियां देख भड़के परिवहन आयुक्त

» तीन दिन में सुधार नहीं तो जवाब देना होगा, लंबित आवेदनों को शून्य करने का आदेश करने का आदेश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के निरीक्षण पर पहुंचे परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने कार्यालय की कई व्यवस्थाओं पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को तीन दिन के भीतर सभी कमियां दूर करने का अल्टीमेटम दिया।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए।निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने विभिन्न पटल, रिकॉर्ड रूम, परमिट शाखा और नागरिक सेवाओं की समीक्षा की।

सारथी और वाहन पोर्टल पर लंबित आवेदनों को शून्य करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जनता को समयबद्ध सेवाएं मिलनी चाहिए।

रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों के बेहतर रखरखाव और व्यवस्थित संधारण पर भी जोर दिया गया। परिवहन आयुक्त ने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है।

उन्होंने आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण सुविधा के कम उपयोग पर चिंता जताते हुए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। निरीक्षण के बाद विभागीय अधिकारियों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हलचल तेज हो गई है।

कथावाचक केस में नया ट्विस्ट

आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ भाई ही पहुंचा एसएसपी दरबार

» पवन देव महाराज से धन उगाही की साजिश का आरोप, महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। चर्चित कथावाचक पवन देव महाराज पर लगे दुष्कर्म के आरोपों के बीच मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोप लगाने वाली महिला के भाई ने ही अब अपनी बहन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर सौंप दी है।

महिला के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वह पवन देव महाराज पर झूठे आरोप लगाकर धन उगाही का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कथावाचक ने महिला को शादी का कोई झांसा नहीं दिया और पूरा मामला आर्थिक लाभ लेने की मंशा से खड़ा किया गया है।

में महिला को शातिर और चालाक बताते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। भाई का आरोप है कि पवन देव महाराज को सुनियोजित तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है।

अब पुलिस की नजर दोनों पक्षों के दावों पर है। मामले ने नया मोड़ ले लिया है और सभी की निगाहें जांच के निष्कर्ष पर टिकी हैं।

खाली तिजोरी के लिए रातभर मशक्कत, तीन गिरफ्तार

» लाखों मिलने की उम्मीद में उखाड़ ले गए कैश चेस्ट, तिजोरी निकली खाली

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। कैंट थाना क्षेत्र स्थित सरयू नहर कॉलोनी में अधिशासी अभियंता, लिफ्ट सिंचाई खंड कार्यालय से पुरानी कैश चेस्ट तिजोरी चोरी करने वाले तीन शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त एक सियाज कार, एक महिंद्रा पिकअप और दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं।

पुलिस के अनुसार चोरों ने कैशियर के कमरे से पूरी तिजोरी ही उखाड़ ली थी। उन्हें उम्मीद थी कि तिजोरी में लाखों रुपये की नकदी होगी, लेकिन तिजोरी खोलने पर उनके हाथ निराशा लगी क्योंकि उसमें कोई रकम नहीं थी। बाद में चोरों ने तिजोरी को काटकर फेंक दिया। घटना की सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने जांच और निगरानी के आधार पर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। उनके कब्जे से कटी हुई तिजोरी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। यह चोरी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि चोरों ने जिस तिजोरी के लिए पूरी रात जोखिम उठाया, वह पूरी तरह खाली निकली।

पीओके में हिंसा भड़की, प्रतिबंध के विरोध में उग्र प्रदर्शन, 27 की मौत

'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' पर बैन के बाद रावलकोट में बवाल

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। संगठन के समर्थकों और पाकिस्तानी सुरक्षाबलों के बीच रावलकोट में हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और कई इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हिंसा की शुरुआत उस समय हुई जब संगठन के समर्थक एक अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर इकट्ठा हुए थे। यहां पहले की गोलीबारी में मारे गए एक कार्यकर्ता का शव रखा गया था। प्रदर्शन के दौरान भीड़ और सुरक्षाबलों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। कई स्थानों पर पथराव, आगजनी और नारेबाजी की घटनाएं सामने आईं।

पाकिस्तानी प्रशासन ने हाल ही में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था। इस फैसले के विरोध में संगठन ने 10 जून को मुजफ्फराबाद विधानसभा के बाहर बड़े धरने और प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके पहले भिंबर, मीरपुर, कोटली और पुंछ से होकर एक विशाल मार्च निकालने की योजना भी बनाई गई है।

हालांकि प्रशासन ने इस प्रस्तावित मार्च और धरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब तक 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। प्रशासन का दावा है कि संगठन के कई प्रमुख नेता फिलहाल फरार हैं, लेकिन छोटे स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी रह सकते हैं।

किन इलाकों में सबसे ज्यादा तनाव

- रावलकोट
- मुजफ्फराबाद
- मीरपुर
- कोटली
- पुंछ और भिंबर क्षेत्र

रविवार देर रात रावलकोट में सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। डिविजनल कमिश्नर सरदार वहीद खान के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता अवरुद्ध कर दिया था और अस्पताल परिसर में घुसने की कोशिश की। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को सुरक्षा कारणों से अस्पताल छोड़ना पड़ा। पीओके में बढ़ते विरोध, प्रशासनिक कार्रवाई और प्रस्तावित बंद-चक्का जाम के आह्वान के चलते पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है

क्यों भड़का विवाद

- 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' पर लगाया गया प्रतिबंध विवाद की मुख्य वजह बना।
- संगठन ने इसे राजनीतिक दमन बताते हुए बड़े आंदोलन का ऐलान किया।
- प्रशासन ने इसे सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कार्रवाई की।

प्रशासन ने क्या कदम उठाए

- 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया
- संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती
- प्रस्तावित मार्च और धरने की अनुमति रद्द
- अस्पतालों और सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ाई गई

डीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तहसीलदार पहुंचीं अदालत

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी रमेश रंजन समेत पांच लोगों पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्कालीन तहसीलदार टूंडला एवं वर्तमान में राजस्व परिषद लखनऊ में तैनात राखी शर्मा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मृदुल दुबे ने मंडलायुक्त आगरा मंडल और डीआईजी आगरा रेंज से विस्तृत आख्या तलब करते हुए अगली सुनवाई 12 जून निर्धारित की है।

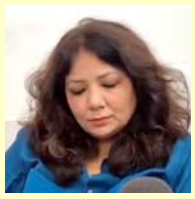

तहसीलदार राखी शर्मा

राखी शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र में तत्कालीन डीएम रमेश रंजन, उनके ओएसडी शैलेंद्र शर्मा, डीएम कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक राजेंद्र खन्ना, एसडीएम कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक अजीत उपाध्याय तथा पेशकार दौजीराम के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने कथित रूप से अवैध धन उगाही के उद्देश्य से अपने कार्यालय में एक विशेष टीम गठित कर रखी थी। आरोप है कि यह टीम विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बिना ठोस कारण नोटिस जारी कराती थी, वेतन रुकवाती थी और बाद में उन्हें दबाव में लेकर धन उगाही का काम करती थी। प्रार्थना पत्र के साथ कथित तौर पर कई आदेशों और दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं। राखी शर्मा का कहना है कि उन्होंने 4 सितंबर 2024 से 16 अप्रैल 2026 तक तहसीलदार टूंडला के पद पर कार्य किया और इस दौरान पूरी निष्ठा के साथ सरकारी दायित्वों का निर्वहन किया। इसके बावजूद उनसे कथित रूप से अवैध धन की मांग की गई। मांग पूरी न करने पर आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही का आरोप लगाकर अप्रैल 2025 का वेतन रोक दिया गया। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि जुलाई माह में उन पर कथित तौर पर जिलाधिकारी को मंथली देने का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, वेतन जारी कराने के बदले आईफोन देने और डीएम आवास पर पहुंचने के लिए भी दबाव डाला गया। आरोप है कि परिस्थितियों के दबाव में उन्हें आईफोन उपलब्ध कराना पड़ा।

मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अब 12 जून को होने वाली सुनवाई में मंडलायुक्त और डीआईजी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

दुबई में भीषण सड़क हादसा सात भारतीय कामगारों की मौत

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में सात भारतीय कामगारों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब तकनीकी खराबी के कारण एक ट्रक अचानक सड़क के बीचोंबीच रुक गया और पीछे से तेज रफ्तार में आ रही मिनीबस उससे जा टकराई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

दुबई पुलिस के यातायात विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर जुमा सलेम बिन सुवैदान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ट्रक में तकनीकी खराबी आने की बात सामने आई है। खराबी के चलते ट्रक चालक वाहन को सड़क किनारे नहीं ले जा सका और वह मुख्य मार्ग पर ही रुक गया। इसी दौरान पीछे से आ रही मिनीबस चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सीधे ट्रक से टकरा गई। पुलिस के अनुसार मिनीबस चालक ने सुरक्षित दूरी का पालन नहीं किया था, जिससे हादसा और गंभीर हो गया।

हादसे में सात भारतीय कामगारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हुए हैं। घायलों में पांच की हालत

➪ **तकनीकी खराबी से बीच सड़क पर रुका ट्रक, पीछे से आ रही मिनीबस टकराई, नौ घायल, पांच की हालत गंभीर**

बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें दुबई के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चार अन्य घायलों को सामान्य चोटें आई हैं और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया है और प्रभावित भारतीय नागरिकों तथा उनके परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय मिशन के अधिकारी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले और उनके उपचार की जानकारी ली।

दुबई पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। ट्रैफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। वहीं, बचाव दल ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सामान्य कर दिया है। हादसे के बाद दुबई में रह रहे भारतीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com